

## उत्तराखण्ड में ग्रामीण पलायन का परिदृश्य एवं प्रभावों का एक भौगोलिक अध्ययन

विकास सिंह राणा

सहायक प्राध्यापक (भूगोल)

राजकीय महाविद्यालय उफरैखाल पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

### शोध सार

उत्तराखण्ड राज्य का पहाड़ी इलाका हरियाली, सुंदर नजारों और तरह-तरह के वन्यजीवों से समृद्ध है, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। इस इलाके में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को अपनाया जा सकता है। यह न केवल आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में गरीबों, महिलाओं और कम पढ़े-लिखे या बिना हुनर वाले लोगों की आजीविका सुधारने का एक अच्छा जरिया भी बन सकता है। पलायन को कम करने के लिए इसे आधुनिक और तकनीकी रूप से नए तरीकों से जोड़ने की जरूरत है। पलायन से बदलाव जनसंख्या भूगोल के मुख्य विषय हैं। अन्य सामाजिक विषयों में, पलायन और भौगोलिक बदलावों के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन उस विषय के मूल सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। यह अध्ययन हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड में ग्रामीण पलायन और जनसांख्यिकीय पैटर्न (बदलावों) के बीच संबंधों की जांच करता है। यहाँ जीवन-निर्वाह कृषि भोजन और ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत है, जबकि खेती योग्य भूमि बहुत कम है और फसल की उत्पादकता भी बहुत कम है। जीवन-निर्वाह अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, वयस्क पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा आजीविका, रोजगार और बुनियादी जरूरतों की तलाश में पहाड़ी इलाकों से बाहर पलायन करने को मजबूर होता है। उत्तराखण्ड के पहाड़ी इलाके में लगभग 48% आबादी रहती है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.08% है, जबकि राज्य की 52% आबादी बहुत कम भौगोलिक क्षेत्र (13.92% क्षेत्रफल) में रहती है। साथ ही, बुनियादी सुविधाओं (संचार, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएँ) की कमी, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएँ ग्रामीण कामकाजी आबादी के पलायन के मुख्य कारण बन रहे हैं। हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि दर अन्य मैदानी क्षेत्रों से भिन्न रही हैं। एक विश्लेषण के अनुसार, राज्य के 11 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ी है, जबकि पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में जनसंख्या वृद्धि का परिदृश्य विरोधाभासी एवं चिन्ताजनक है क्योंकि यहाँ जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर बढ़ने की बजाय 2011 की जनगणना में कमी दर्ज की गई है। जिसका प्रमुख कारण पलायन को ही माना जा सकता है। उत्तराखण्ड में पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में सबसे अधिक संख्या में ऐसे गाँव हैं जहाँ कोई नहीं रहता (घोस्ट विलेज)। आम तौर पर, नकारात्मक वृद्धि विकास, जनसांख्यिकीय संरचना और जनसंख्या वितरण के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है।

**मुख्य शब्दः—** भौगोलिक क्षेत्र, आजीविका, रोजगार, अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधायें, ग्रामीण पलायन आदि।

### प्रस्तावना

पलायन और जनसांख्यिकीय बदलाव जनसंख्या भूगोल के मुख्य विषय हैं और जनसंख्या की गतिशीलता का अध्ययन समय और स्थान के संदर्भ में किया जाता है। यह एक भौगोलिक या स्थानिक गतिशीलता है जिसमें एक

भौगोलिक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और निवास स्थान बदलने की प्रक्रिया शामिल होती है। साथ ही, इसका सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो जनसंख्या के आकार से जुड़े होते हैं। किसी भी इलाके की आबादी पर असर डालने वाले कारक के तौर पर माइग्रेशन (प्रवास) को जाना जाता है और किसी भी क्षेत्र में डेमोग्राफिक बदलाव प्रजननता (जन्म दर), मृत्युता (मृत्यु दर) और प्रवास (बाहर जाने या अंदर आने) पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, किसी भी इलाके की इंसानी आबादी ज्यादा जन्म और बाहर से लोगों के आने (आप्रवास) से बढ़ती है, जबकि ज्यादा मौतों और लोगों के बाहर जाने (उत्प्रवास) से घटती है। इसलिए, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि किसी भी इलाके में आबादी का स्वरूप (डेमोग्राफिक बदलाव) तय करने में प्रवास अहम भूमिका निभाता है। वैश्वीकरण और बढ़ती संचार प्रणाली के इस दौर में, प्रवास पहले से कहीं ज्यादा देशों को प्रभावित कर रहा है और विकास योजना बनाने वालों के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है, जबकि जनसंख्याविद् आबादी का अनुमान लगाते समय इसके उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं।

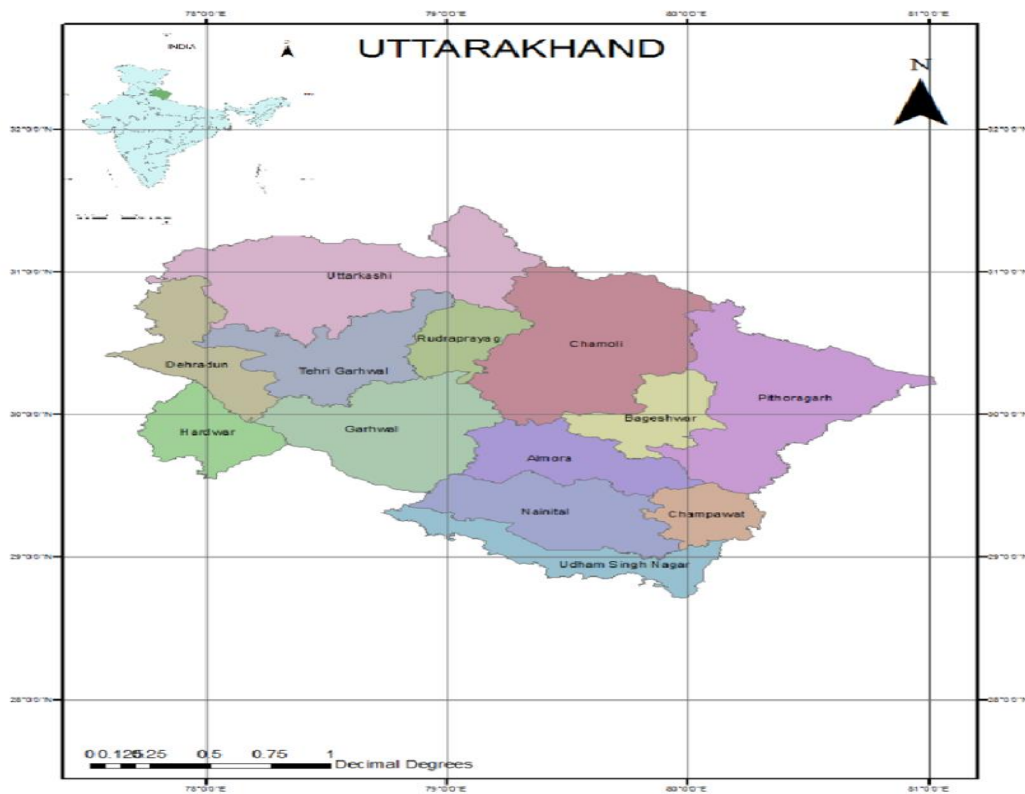
## शोध प्रविधि

किसी भी शोध कार्य का विधि तंत्र अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग होता है। डेटा इकट्ठा करने के तरीके और विश्लेषण अध्ययन के लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी डेटा, जानकारी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए उपयुक्त तकनीकों, तरीकों और साधनों का इस्तेमाल किया गया है। इन मुद्दों को समझने के लिए, पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में पलायन के पैटर्न का विश्लेषण करने के उद्देश्य से इस शोध पत्र में बताया गया कि उत्तराखंड से पलायन के पैटर्न को समझने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है। पलायन के मुख्य कारणों और जनसंख्या में बदलाव पर उनके असर के बारे में जानकारी एकेडमिक साहित्य, सरकारी डेटा स्रोतों, फील्ड वर्क और खुद के अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) के जरिए इकट्ठा की गई है। इसके अलावा, अलग-अलग ऑफिस और हाल ही में छपी रिपोर्टों से मिले डेटा का इस्तेमाल करके अध्ययन क्षेत्र में प्रवास के प्रतिरूप को समझा गया है। 2001 और 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से इकट्ठा किए गए जनांकिकीय और दूसरे जरूरी सामाजिक आंकड़ों का विश्लेषण और वेरिफिकेशन किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के लिये भारत की जनगणना, जिला जनगणना पुस्तिका, की रिपोर्टों का गहनता से विश्लेषण किया गया है। साथ ही, यह अध्ययन पहाड़ी इलाकों में प्रवास के प्रतिरूप और उसके सामाजिक-आर्थिक असर को समझने में मदद करती है।

## अध्ययन क्षेत्र

उत्तराखण्ड भारत का 27वाँ राज्य है जिसकी स्थापना 09 नवम्बर सन् 2000 को हुई थी। उत्तराखण्ड राज्य 28°43' से 31°27' उत्तरीय अक्षांशों तथा 77°34' से 81°02' पूर्वी देशान्तरों के बीच स्थित है। यह उत्तर में तिब्बत क्षेत्र, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश राज्य तथा दक्षिण पश्चिम में हरियाणा राज्य से घिरा है। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी० है। उत्तराखण्ड को गढ़वाल तथा

कुमाँऊ दो मुख्य भागों में बाँटा गया है। उत्तराखण्ड में कुल 13 जिले हैं जिनमें से सात जिले उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून तथा हरिद्वार गढ़वाल में तथा छः जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर कुमाँऊ में स्थित हैं। उत्तराखण्ड के जिलों में दो जिले हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर पूर्ण रूप से मैदानी हैं, दो जिले देहरादून तथा नैनीताल पर्वतीय-मैदानी हैं तथा शेष नौ जिले पर्वतीय हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या 10086292 है। जिसमें 5137773 पुरुष तथा 4948519 स्त्री जनसंख्या है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी<sup>0</sup> है। राज्य की 69.77% जनसंख्या ग्रामीण तथा 23.23% जनसंख्या नगरीय है।



### अध्ययन क्षेत्र का मानचित्र

#### ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का परिदृश्य

पहाड़ी इलाकों के लोग अपनी आजीविका के लिए गुजारे लायक खेती (सब्सिस्टेंस फार्मिंग), पशुपालन और छोटे पैमाने के व्यापार व मजदूरी से होने वाली आय पर निर्भर रहते हैं। इस क्षेत्र में गुजारे लायक खेती भोजन और ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत है, खेती के योग्य जमीन बहुत कम है और फसल की पैदावार भी बहुत कम है। गुजारे लायक अर्थव्यवस्था पर निर्भरता और स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त मौकों की कमी के कारण, बड़ी संख्या में वयस्क पुरुष आबादी को आजीविका और रोजगार की तलाश में पहाड़ी इलाकों से बाहर जाना पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं (संचार, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएँ) की कमी, बदलते मौसम और प्राकृतिक

आपदाएँ ग्रामीण कामकाजी आबादी के बाहर की ओर प्रवास के मुख्य कारण बन रहे हैं। इसलिए, पहाड़ी इलाकों से प्रवास आम बात है और यह जिलों – अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चंपावत और नैनीताल में बसे पहाड़ी ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर लोगों के लिए आजीविका का मुख्य तरीका है। 1990 के दशक में, पहाड़ी इलाकों से पलायन व्यक्तिगत और अस्थायी होता था, यानी हर परिवार से एक या दो लोग शहरों में अलग-अलग कामों में लगे होते थे और वे अपनी कमाई मनी-ऑर्डर से घर भेजते थे। इसीलिए इस व्यवस्था को मनी-ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता था और 42 से 57% परिवारों में कम से कम एक सदस्य बाहर जाकर काम करता था। लेकिन मौजूदा हालात में, व्यक्तिगत अस्थायी पलायन के मुकाबले पलायन बढ़ा है। स्थायी पारिवारिक पलायन में, लोग अपने परिवारों को ग्रामीण इलाकों से शहरों में स्थायी रूप से ले जा रहे हैं 48% परिवारों ने बाहर पलायन की सूचना दी और 34% ने लंबे समय तक बाहर रहने की बात कही। माइग्रेशन (प्रवास) के मामले में, 16% लोगों ने स्थायी प्रवास और 4% ने कम समय के लिए प्रवास की बात कही।

आज प्रवास के बदलते प्रतिरूप के कारण, उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी घटने की स्थिति पैदा हो गई है। वयस्क आबादी के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण, राज्य प्रवास आयोग ने 2018 में कुछ गांवों को घोस्ट विलेज (खाली हो चुके गांव) घोषित किया। एक विश्लेषण के अनुसार, राज्य के दो जिलों पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी की दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक रही है (क्रमशः -1.41) और (-1.28)। पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में बिना आबादी वाले गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है।

साथ ही, राज्य की डेमोग्राफिक संरचना (जनसांख्यिकीय बनावट) में भी काफी बदलाव देखे गए हैं, खासकर 2001-2011 के दशक में, जो तेज आर्थिक विकास का दौर था। इस दशक में राज्य की आबादी में औसत वृद्धि (1.74% प्रति वर्ष) दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत (1.47% प्रति वर्ष) से ज्यादा है। इसी तरह, मैदानी जिलों (2.82%) की तुलना में राज्य के पहाड़ी इलाकों में आबादी की वृद्धि दर (0.70%) काफी कम रही। इसके अलावा, पहाड़ी जिलों के ग्रामीण इलाकों में 2001-2011 के दौरान आबादी में सबसे कम वृद्धि (0.38%) दर्ज की गई। लगभग 66.7% लोगों ने राज्य के शहरी केंद्रों (मुख्य रूप से देहरादून) की ओर पलायन किया और 33.3% लोगों ने दूसरे राज्यों के शहरी केंद्रों की ओर पलायन किया। प्रशासनिक तौर पर इस अध्ययन क्षेत्र को 13 जिलों में बांटा गया है, जिनमें से 9 जिले पहाड़ी इलाकों वाले हैं और बाकी 4 जिलों में कुछ या पूरी तरह से मैदानी इलाके हैं।

पहाड़ी इलाके का क्षेत्रफल 86.08% है, जबकि मैदानी इलाके का क्षेत्रफल लगभग 13.92% है। पहाड़ों और मैदानों के बीच इस भौगोलिक असमानता ने राज्य को मुख्य रूप से ज्यादा विकसित और कम विकसित क्षेत्रों में बांट दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल आबादी 1,00,86,292 है और आबादी का घनत्व 189 व्यक्ति

प्रति वर्ग किलोमीटर है साथ ही, लगभग 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है।

### पलायन के प्रभावों का विश्लेषण

उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से बाहर की ओर प्रवास का चलन यह देखा गया है कि प्रवास और जनसांख्यिकी बदलावों के बीच गहरा संबंध है प्रवास में कोई भी बदलाव किसी भी इलाके की डेमोग्राफी को बदल सकता है, जो खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जनसांख्यिकी प्रतिरूप पर असर डालने वाले मुख्य कारणों में से एक है। यहां रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के मौके कम हैं और बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश और बुनियादी सुविधाओं व आजीविका के लिए यहां से बाहर पलायन कर गए हैं। तराई इलाके (मैदानी इलाका) को राज्य का फूड बाउल (अन्न का भंडार) भी कहा जाता है और यहां रोजगार के कई मौके हैं क्योंकि ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां मैदानी इलाकों में केंद्रित हैं, जिससे राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों के बीच आय में भारी असमानता पैदा हुई है, जो पहाड़ी इलाकों के लोगों को अपनी ओर खींचती है। पहाड़ी इलाकों में प्रति व्यक्ति नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन (NDDP) मैदानी इलाकों की तुलना में कम है। एक अनुमान के मुताबिक, 2017–18 में राज्य में औसत प्रति व्यक्ति NDDP 157.4 हजार रुपये था। पूरे राज्य में, मैदानी इलाके के जिलों – हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में प्रति व्यक्ति NDDP ज्यादा दर्ज किया गया, जो क्रमशः 254.1, 195.9 और 187.3 हजार रुपये है। हरिद्वार जिले में प्रति व्यक्ति NDDP सबसे ज्यादा 254.1 हजार रुपये है और रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम प्रति व्यक्ति NDDP 83.5 हजार रुपये दर्ज किया गया। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के अलावा, बाकी सभी जिलों में प्रति व्यक्ति NDDP राज्य के औसत से काफी कम है।

उत्तराखंड के खेती-बाड़ी पर आधारित अर्थव्यवस्था की सीमाओं के कारण, पहाड़ी इलाकों के एक बड़े हिस्से से ग्रामीण पुरुष युवा पारंपरिक रूप से रोजगार के नए मौकों की तलाश में बाहर चले गए हैं विशेष रूप से अल्मोड़ा (14.2%), पौड़ी गढ़वाल (13.9%) और टिहरी गढ़वाल (13.1%) से। बाहर गए लोगों ने पहाड़ों में रह रहे अपने परिवारों को जो पैसे (रेमिटेंस) भेजे, वे ज्यादातर ग्रामीण आबादी के लिए नकद आय और भोजन खरीदने की क्षमता का मुख्य स्रोत बने। पुरुष युवाओं के बाहर जाने (आउट-माइग्रेशन) में बढ़ोतरी ने न केवल पहाड़ी खेती और संसाधन विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बढ़ाकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, बल्कि उस समृद्ध पारंपरिक ज्ञान को भी कमजोर किया है जिसे ग्रामीण समुदायों ने प्रकृति के साथ लंबे प्रयोगों से विकसित किया था। पहाड़ी इलाकों की महिलाओं को अक्सर प्राथमिक संसाधन विकासकर्ता माना जाता है। साथ ही, खेती और अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए वयस्क पुरुष मजदूरों की भारी कमी है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद अलग-अलग कारकों और बाधाओं का कुल असर यह है कि लोगों को घोर गरीबी, मुश्किलों, असुरक्षा के लगातार डर, लाचारी की भावना और बाहरी मदद पर पूरी तरह निर्भरता का सामना करना पड़ता है।

पहाड़ी जिलों के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय के लिए पलायन (माइग्रेशन) का प्रतिशत सबसे ज्यादा 9.8% है, जबकि मैदानी जिलों के ग्रामीण इलाकों में यह बहुत कम, यानी 0.5% है। इसी तरह, पहाड़ी इलाकों के शहरी क्षेत्रों में लंबे समय के लिए पलायन करने वालों की संख्या 0.7% है, जो ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, यह अध्ययन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर पलायन की दिशा को दर्शाता है।

पलायन और जनसंख्या में बदलाव सांख्यिकी डायरी (2018–19) के अनुसार, पहाड़ी जिलों की दशक-दर-दशक विकास दर 12.75% है, जो बहुत कम है। जबकि ऊधम सिंह नगर और देहरादून सहित मैदानी जिलों में यह दर 31.93% है, जो पहाड़ी इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसी तरह, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 बताता है कि राज्य की 69.77% आबादी ग्रामीण है, जिसमें से 67.90% पहाड़ी जिलों में रहती है। 2001 की जनगणना की तुलना में, पहाड़ी जिलों की आबादी 2011 की जनगणना में 68.40% से घटकर 65% हो गई है। ऐसा आजीविका के सीमित अवसरों, अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी, कठोर मौसम, बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और मानव-पशु संघर्ष के कारण हुआ है। मैदानी इलाकों के जिलों (ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल) में 2001 और 2011 के दो लगातार दशकों में आबादी बढ़ने की दर पहाड़ी जिलों की तुलना में बहुत ज्यादा रही है। वही पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में आबादी बढ़ने की दर नकारात्मक रही है, जो क्रमशः -1.41 और -1.28 है। इसके अलावा, पलायन की समस्या से निपटने के लिए टिकाऊ विकास जरूरी है। पलायन से जुड़े मौजूदा और तत्काल खतरों का सामना करने के लिए इसे एक बेहतर विकल्प माना गया है। इसे हासिल करने के लिए, पहाड़ी खेती की प्रणाली को पहाड़ी विकास के समग्र, एकीकृत और अनुकूलनीय ढांचे का एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए। इसलिए, पहाड़ी खेती की गतिविधियों को गरीबी मिटाने के मौजूदा कार्यक्रमों, आजीविका सुधार की रणनीतियों और ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

## निष्कर्ष

प्रवास इंसानों की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, लेकिन आजकल आबादी में बदलाव के कारण यह नीति बनाने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। साथ ही, असंतुलित विकास के कारण पूरे राज्य में असमानता के लिए भी यही जिम्मेदार है। भोजन और आजीविका की असुरक्षा के बढ़ते खतरों ने इस क्षेत्र से ग्रामीण युवाओं के बाहर जाने आउट-माइग्रेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर बाहर जाने का बढ़ता चलन, जो आबादी में बदलाव के लिए जिम्मेदार है, ने ग्रामीण जीवन की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गुणवत्ता को प्रभावित किया है और साथ ही ग्रामीण महिलाओं की जिम्मेदारियों, कठिनाइयों और काम के बोझ को भी बढ़ाया है। यह शोध पत्र दिखाता है कि ज्यादातर लोग आजीविका और रोजगार के अवसरों की तलाश में बाहर गए माइग्रेशन कमीशन ने भी 2018 की अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात पर विचार किया है।

उत्तराखण्ड में जनसंख्या परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में है। राज्य में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में 18.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें क्षेत्रीय आधार पर पर्याप्त अंतर मिलता है। जिसका सबसे बड़ा कारण अन्तर्राज्यीय प्रवास है। प्रायः यह देखने में आया है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय भागों से मैदानी (तराई) क्षेत्रों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है तथा पर्वतीय क्षेत्रों के कई गाँव खाली हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण अच्छी सम्भावनाओं की तलाश माना जा सकता है। उत्तराखण्ड की जनसंख्या 2001 में लगभग 84 लाख थी जो कि 2011 में बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो चुकी है।

यदि उत्तराखण्ड की जनसंख्या के जनगणना 2011 आंकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट है कि राज्य के 11 जिलों में जनसंख्या वृद्धि धनात्मक रही है जबकि 2 जिलों अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल में यह ऋणात्मक है, जिसका तात्पर्य यह है कि विगत एक दशक में दोनों जिलों की जनसंख्या कम हुई है। जनगणना के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 12.75 प्रतिशत है जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह लगभग 32 प्रतिशत है। जिसका मूल कारण मैदानी क्षेत्रों में होने वाला नगरीकरण, औद्योगिक विकास तथा पड़ोसी राज्यों से होने वाला प्रवाजन है। विगत दशक में राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला ऊधमसिंह नगर रहा है जो कि मैदानी क्षेत्र में स्थित है तथा यहाँ पर औद्योगिक विकास तथा कृषि की लाभदेयता उत्तम है। देहरादून तथा हरिद्वार दो अन्य उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के मुख्य कारण पर्वतीय क्षेत्रों होने वाला पलायन, मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति, अन्य राज्यों से होने वाला प्रवाजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की उपलब्धता आदि हैं।

पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण पलायन को माना जा सकता है क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर आदि मैदानी नगरों की ओर प्रवासित हुए हैं। इनके प्रवास का मुख्य कारण रोजगार के साधनों की कमी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, पेयजल समस्या विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ आदि हैं।

यदि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परिवहन संचार की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाये तो उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पायी जाने वाली जनसंख्या वृद्धि की विषमता कम हो सकती है। साथ ही राज्य में होने वाले अन्तर्राज्यीय पलायन को कम किया जा सकता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अवस्थी आई.सी., उत्तराखंड की पहाड़ी अर्थव्यवस्था में माइग्रेशन के पैटर्न फील्ड जांच से सबूत, इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, 57(4), 84–99 (2010)
- बोरा आर.एस., हिमालयी क्षेत्रों से बाहर की ओर माइग्रेशन, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन (1996)
- डी-पॉपुलेशन (जनसंख्या में कमी) के रुझान, पैटर्न और प्रभाव – उत्तराखंड, भारत (कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार)। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, काठमांडू, नेपाल, ICIMOD (2017)

- अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड राज्य की मानव विकास रिपोर्ट, 125–126 (2018)
- अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार, सांख्यिकीय डायरी उत्तराखंड 2011–12,
- अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकीय डायरी उत्तराखंड (2018–19)
- गोल्डशीडर सी., माइग्रेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर एनालिटिक इश्यूज एंड कम्पैरेटिव पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपिंग नेशंस, सोशियोलॉजिकल फोरम, 2(4), 674–696 (1987)
- इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM), जिनेवा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट (2018)